

Long Questions

1. Discuss John Austin's theory of law as "Command of the Sovereign".
 2. Critically analyse the limitations of Austin's "Command Theory" in the modern democratic framework.
-

John Austin's Theory of Law as "Command of the Sovereign"

Introduction

John Austin (1790–1859), a jurist of the **Analytical School of Jurisprudence**, defined law as the **command of the sovereign backed by sanction**. His theory, also called the **Command Theory of Law**, was the first systematic attempt to separate **law from morality, customs, and religion**.

Meaning of Law According to Austin

Austin's famous definition:

"Law is a command of the sovereign, backed by a sanction."

Thus, law consists of:

1. **Command** → An order given by a superior to an inferior.
 2. **Duty** → Command imposes an obligation to obey.
 3. **Sanction** → Consequences (punishment) for disobedience.
 4. **Sovereign** → The supreme authority, habitually obeyed by the people, but not subject to any other authority.
-

Key Elements of Austin's Theory

1. **Command**
 - A wish or desire expressed by a political superior.
 - Example: "Pay tax" → command of State.
2. **Duty**
 - The person to whom the command is directed has a **legal duty** to obey.
3. **Sanction**
 - Non-compliance attracts punishment.
 - Example: Not paying income tax → penalty under law.
4. **Sovereign**
 - The person or body of persons whom society habitually obeys.
 - In a democracy → Parliament and Government (but limited by Constitution).

Illustration

- “Do not commit theft” → Command of sovereign.
 - Creates duty on citizens.
 - Sanction → punishment under IPC.
-

Merits of Austin's Theory

1. Clear, simple, and scientific definition of law.
 2. Separates law from **morality and religion**.
 3. Useful in explaining **criminal law and penal system**.
-

Criticism of Austin's Theory

1. **Rigid and outdated** – Cannot explain modern constitutional democracies.
 2. **No place for morality** – Ignores justice, ethics, natural rights.
 3. **Fails in international law** – No sovereign above States, yet international law is obeyed.
 4. **Habitual obedience problem** – In democracies, sovereignty lies with the **Constitution and people**, not one authority.
 5. **Customary laws** – Many legal systems derive from customs, not from sovereign commands.
-

Case References

- **State of West Bengal v. Union of India (1963)** → SC held sovereignty is with the **Constitution**, not Parliament alone, rejecting Austin's absolute sovereign idea.
 - **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)** → Parliament's law-making power limited by **Basic Structure Doctrine**, showing that sovereign power is not unlimited.
-

Conclusion

Austin's **Command Theory** was a landmark in defining law as a science, independent of morality. However, it is too rigid for modern times, as sovereignty today is **divided and constitutional**. Despite its limitations, Austin's theory remains foundational in legal positivism and an important milestone in jurisprudence.

- जॉन ऑस्टिन का “सर्वोच्च सत्ता का आदेश” सिद्धांत
 - ◆ परिचय

जॉन ऑस्टिन (1790–1859) विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र (Analytical School of Jurisprudence) के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने कानून को “सर्वोच्च सत्ता (Sovereign) का आदेश, जिसके साथ दंड (Sanction) जुड़ा हो” के रूप में परिभाषित किया। यह सिद्धांत *Command Theory of Law* के नाम से प्रसिद्ध है। ऑस्टिन पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने कानून को नैतिकता, धर्म और परंपरा से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

◆ ऑस्टिन के अनुसार कानून की परिभाषा

ऑस्टिन ने कहा —

“Law is a command of the sovereign, backed by a sanction.”

“कानून सर्वोच्च सत्ता का वह आदेश है जिसके पालन न करने पर दंड मिलता है।”

अतः कानून के चार मुख्य तत्व हैं —

1. **आदेश (Command)** — उच्च सत्ता द्वारा अधीन व्यक्ति को दिया गया निर्देश।
 2. **कर्तव्य (Duty)** — आदेश से पालन का दायित्व उत्पन्न होता है।
 3. **दंड (Sanction)** — आदेश न मानने पर दंड या परिणाम।
 4. **सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)** — वह सत्ता जिसे समाज सामान्यतः मानता है और जो किसी अन्य के अधीन नहीं है।
-

◆ सिद्धांत के मुख्य तत्व

1. **आदेश (Command)**
 - राजनीतिक श्रेष्ठ (Political Superior) की इच्छा या निर्देश।
 - उदाहरण: “कर चुकाओ” — राज्य का आदेश।
 2. **कर्तव्य (Duty)**
 - जिस पर आदेश लागू होता है, उस पर पालन का कानूनी दायित्व बनता है।
 3. **दंड (Sanction)**
 - आदेश का उल्लंघन करने पर दंड या दायित्व।
 - उदाहरण: आयकर न देना → दंड या जुर्माना।
 4. **सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)**
 - वह व्यक्ति या संस्था जिसे समाज नियमित रूप से मानता है।
 - लोकतंत्र में संसद और सरकार, परंतु संविधान की सीमाओं में।
-

◆ उदाहरण

“चोरी मत करो” → सर्वोच्च सत्ता का आदेश।

इससे नागरिकों पर कर्तव्य उत्पन्न होता है, और उल्लंघन पर IPC के अंतर्गत दंड मिलता है।

◆ ऑस्टिन सिद्धांत की विशेषताएँ

1. स्पष्ट, सरल और वैज्ञानिक परिभाषा।
 2. कानून को नैतिकता और धर्म से अलग करता है।
 3. आपराधिक कानून और दंड प्रणाली को समझाने में उपयोगी।
-

◆ आलोचनाएँ (Criticisms)

1. **कठोर और पुराना सिद्धांत** – आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र पर लागू नहीं होता।
 2. **नैतिकता की उपेक्षा** – न्याय, आचार और प्राकृतिक अधिकारों को नज़रअंदाज़ करता है।
 3. **अंतरराष्ट्रीय कानून पर लागू नहीं** – वहाँ कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं, फिर भी पालन होता है।
 4. **आदतन आज्ञापालन (Habitual Obedience)** – लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता संविधान और जनता में निहित है, किसी व्यक्ति में नहीं।
 5. **रीति-रिवाज आधारित कानून** – कई कानून परंपराओं से बने हैं, किसी आदेश से नहीं।
-

◆ प्रमुख न्यायिक दृष्टांत

- **State of West Bengal v. Union of India (1963)** → सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रभुता संविधान में निहित है, केवल संसद में नहीं।
 - **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)** → संसद की शक्ति “मूल संरचना सिद्धांत” से सीमित है, जिससे सिद्ध होता है कि सर्वोच्च सत्ता निरंकुश नहीं है।
-

◆ निष्कर्ष

ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत कानून को नैतिकता से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक प्रयास था। परंतु आज के संवैधानिक युग में जहाँ सत्ता विभाजित और सीमित है, यह सिद्धांत अत्यधिक कठोर माना जाता है। फिर भी, “कानूनी प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism)” की नींव रखने में ऑस्टिन का योगदान अमूल्य और स्थायी है।

■ आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऑस्टिन के “आदेश सिद्धांत” की सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण

◆ परिचय

जॉन ऑस्टिन ने कानून को “सर्वोच्च सत्ता का आदेश” (Command of the Sovereign) कहा, जो दंड (Sanction) द्वारा समर्थित होता है। यह सिद्धांत कानून को नैतिकता, धर्म और परंपरा से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करता है। किंतु आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जहाँ **संविधान सर्वोच्च** है और सत्ता विभाजित है, वहाँ ऑस्टिन का यह सिद्धांत कई सीमाओं से ग्रस्त है।

◆ ऑस्टिन के सिद्धांत का सार

ऑस्टिन के अनुसार —

“Law is a command of the sovereign, backed by a sanction.”

अर्थात् कानून वह आदेश है जो सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया हो और जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो।

इस परिभाषा में चार प्रमुख तत्व हैं —

1. आदेश (Command)
 2. कर्तव्य (Duty)
 3. दंड (Sanction)
 4. सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)
-

◆ आधुनिक लोकतंत्र में सिद्धांत की सीमाएँ

1. संविधान सर्वोच्च है, व्यक्ति नहीं

- आधुनिक लोकतंत्रों में “सर्वोच्च सत्ता” किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि **संविधान** में निहित है।
- भारत में संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका — सभी संविधान द्वारा सीमित हैं।
- अतः कोई भी संस्था “निरंकुश सर्वोच्च सत्ता” नहीं कही जा सकती।

2. जनसत्ता (Popular Sovereignty)

- लोकतंत्र में असली सत्ता जनता के पास होती है।
- जनता केवल अस्थायी रूप से सत्ता प्रतिनिधियों को सौंपती है, जो ऑस्टिन की “habitual obedience” की अवधारणा से भिन्न है।

3. विधायी, कार्यकारी और न्यायिक विभाजन

- सत्ता का विभाजन (Separation of Powers) ऑस्टिन के एकात्मक (Unitary) विचार के विपरीत है।
- प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखता है।

4. नैतिकता और न्याय की भूमिका

- आधुनिक कानून केवल दंड या आदेश नहीं, बल्कि **न्याय, मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों** पर आधारित हैं।

- ऑस्टिन का सिद्धांत इन मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है।

5. अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन

- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई “सर्वोच्च सत्ता” नहीं है, फिर भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं।
- यह ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को चुनौती देता है।

6. परंपरागत और न्यायनिर्मित कानून (Custom & Case Law)

- कई कानून समाज की परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं से बनते हैं, न कि किसी आदेश से।
- उदाहरण: कॉमन लॉ प्रणाली।

◆ न्यायिक दृष्टिकोण

- **State of West Bengal v. Union of India (1963)** — सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रभुता संविधान में निहित है, संसद में नहीं।
- **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)** — संसद की शक्ति “मूल संरचना सिद्धांत” से सीमित है।
इन दोनों मामलों ने ऑस्टिन की “असीमित सर्वोच्च सत्ता” की धारणा को अस्वीकार किया।

◆ निष्कर्ष

ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत अपने समय में क्रांतिकारी था, जिसने कानून को वैज्ञानिक और नैतिकता से स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया।

परंतु आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में यह सिद्धांत सीमित, कठोर और अप्रासंगिक प्रतीत होता है क्योंकि —

- यहाँ सत्ता संविधान और जनता में निहित है,
- और कानून का उद्देश्य केवल आदेश पालन नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा है।

फिर भी, यह सिद्धांत “कानूनी प्रत्यक्षवाद” (Legal Positivism) की नींव बनाकर आज भी न्यायशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्तंभ है।
